Source: https://ndtv.in/jobs/nhrc-online-short-term-internship-march-2026-how-to-apply-10790427

NHRC Online Internship 2026: मानवाधिकार आयोग में इंटर्नशिप का बड़ा मौका, इतना मिलेगा स्टाइपेंड

NHRC ने मार्च 2026 के लिए ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप (OSTI) शुरू की है. ये उन इंटर्नशिप छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए है, जो मानवाधिकार सीखना और असली केस स्टडी अनुभव करना चाहते हैं. जानिए कब तक है लास्ट डेट और कैसे अप्लाई करें.

Edited by:मुकेश बौड़ाई | जनवरी 20, 2026 14:19 pm IST
Published Onजनवरी 20, 2026 12:37 pm IST
Last Updated Onजनवरी 20, 2026 14:19 pm IST

NHRC में इंटर्नशिप का मौका

NHRC Online Short Term Internship 2026: अगर आप मानवाधिकार के बारे में सीखना चाहते हैं और इसे असली दुनिया में देखने का मौका चाहिए, तो NHRC की ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप (Online Short-Term Internship) आपके लिए एक बढ़िया मौका है. यह इंटर्नशिप खास तौर पर छात्रों और रिसर्स करने वालों के लिए है, ताकि उन्हें मानवाधिकार के अहमियत और असली केस स्टडीज समझ में आ सकें. यह ऑनलाइन प्रोग्राम 9 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक चलेगा. जानिए इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या फायदा होगा..

इंटर्नशिप की डेट्स और टाइम

यह प्रोग्राम 9 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा और इसका टाइम सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा. इस दौरान आपको पूरे टाइम ऑनलाइन मौजूद रहना होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2026 शाम 6 बजे है, इसलिए टाइम रहते अप्लाई करना जरूरी है.

कौन कर सकता है अप्लाई

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं
कोई भी 5 साल का PG कोर्स कर रहे तीसरे साल के छात्र या उससे ऊपर
ग्रेजुएशन के तीसरे या आखिरी साल के छात्र
PG डिग्री या डिप्लोमा के किसी भी साल के छात्र
3 साल का LL.B प्रोग्राम कर रहे छात्र
किसी भी विषय में रिसर्च कर रहे रिसर्चर

इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी

आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 28 साल से कम होनी चाहिए.
क्लास 12 और उसके बाद सभी सेमेस्टर में कम से कम 60% अंक होने चाहिए.
जो पहले से NHRC की इंटर्नशिप कर चुके हैं, वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं.

अप्लाई कैसे करें

इंटर्नशिप के लिए अप्लाई सिर्फ NHRC की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन किया जाएगा. आपको एक छोटा सा 250 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (Statement of Purpose) देना होगा, जिसमें बताएं कि आप इस इंटर्नशिप में क्यों शामिल होना चाहते हैं. इसके अलावा 10वीं से लेकर अब तक की सभी मार्कशीट्स स्कैन करके अपलोड करनी होंगी. इसके साथ ही आपको अपने HOD, डीन या प्रिंसिपल का रिकमेंडेशन लेटर देना होगा, जो विज्ञापन के बाद की तारीख का होना चाहिए.

इंटर्नशिप में क्या सीखने को मिलेगा

इंटर्नशिप के दौरान आपको NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स के साथ इंटरएक्टिव सेशन मिलेंगे. इसके अलावा आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. किताबों की समीक्षा करने का मौका भी मिलेगा और आप मानवाधिकार पर बनी फिल्में भी देखेंगे. इनमें बाल मजदूरी, तस्करी, मेंटल हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी फिल्में शामिल हैं. इसके साथ ही, आपको वर्चुअल फील्ड विजिट का एक्सपीरिएंस भी मिलेगा, जैसे जेल, पुलिस स्टेशन, NGOs और शेल्टर होम. इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि मानवाधिकार कैसे असली दुनिया में लागू होते हैं.

इंटर्नशिप पूरा होने पर क्या मिलेगा

इंटर्नशिप पूरी होने पर आपको 2,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा. इसके अलावा, जो समय पर मौजूद रहे, सभी सेशन में हिस्सा लें और प्रोजेक्ट और बुक

रिव्यू समय पर जमा करें, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन (Certificate of Participation) भी मिलेगा. अगर आपको इंटर्नशिप या आवेदन में कोई समस्या आए तो जनरल समस्या के लिए 011-24663371 और टेक्निकल इश्यू के लिए 011-24663294 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

Source: https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/patna/live-updates/nitin-nabin-bjp-president-nitish-kumar-samriddhi-yatra-patna-neet-student-death-case-bihar-news-live-updates/3080046/amp

Bihar Breaking News Highlights: बीजेपी के नए `बॉस` बने नितिन नबीन, बोले- मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं

राज मिश्रा | Jan 20, 2026, 19:21 PM IST

Bihar News Today Highlights: बिहार से ताल्लुक रखने वाले नितिन नबीन की बीजेपी अध्यक्ष पद पर आज (मंगलवार, 20 जनवरी) ताजपोशी होनी है. वे 26 साल की उम्र में विधायक बन गए थे और अब 45 साल की उम्र में भाजपा अध्यक्ष बन चुके हैं. उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार भाजपा के बड़े नेता थे. वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा लेकर आज गोपालगंज जिले पहुंचेंगे, जहां वे करोड़ों रुपये की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे.

Bihar News Today Highlights: बिहार के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है. आज (मंगलवार, 20 जनवरी) के दिन 'बिहार के लाल' नितिन नबीन की बीजेपी अध्यक्ष पद ताजपोशी होने वाली है. सोमवार को ही उन्हें निर्विरोध तौर पर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. सोमवार शाम को इसकी घोषणा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के. लक्ष्मण ने बताया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के पक्ष में 37 सेट नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए. नितिन नबीन के पक्ष में 37 सेट नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे. उनके प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे. वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा लेकर आज गोपालगंज जिले पहुंचेंगे. यहां मुख्यमंत्री करीब एक अरब 92 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 01 अरब 31 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा पटना में नीट छात्रा की मौत मामला अभी तक गरम है. एसआईटी जांच के बीच यह मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास पहुंच गया है. NHRC के वकील एसके झा ने निष्पक्ष जांच के लिए याचिका दायर की है.

Source: https://www.patrika.com/chhatarpur-news/three-days-time-if-ais-standard-check-of-sleeper-buses-is-not-done-then-permit-and-fitness-will-be-stopped-20275945

तीन दिन का समय, स्लीपर बसों की एआइएस मानक जांच नहीं कराई तो परमिट और फिटनेस पर रोक

स्लीपर बसों में लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं और आगजनी की गंभीर घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़ा रुख अपनाया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर अब स्लीपर बसों की एआइएस तकनीकी सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य जांच कराई जाएगी। जांच नहीं कराने वाली बसों पर [...]

2 min read छतरपुर, Dharmendra Singh Jan 20, 2026

स्लीपर बसों में लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं और आगजनी की गंभीर घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़ा रुख अपनाया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर अब स्लीपर बसों की एआइएस तकनीकी सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य जांच कराई जाएगी। जांच नहीं कराने वाली बसों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके परमिट और फिटनेस पर रोक लगाई जाएगी।

इसी क्रम में जिले के एआरटीओ मधु सिंह ने स्लीपर बस ऑपरेटर्स की बैठक आयोजित कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन दिन के भीतर सभी स्लीपर बसों की तकनीकी जांच कराई जाए। बैठक में मौजूद बस ऑपरेटर्स ने विभागीय निर्देशों का पालन करने और बसों की जांच कराने पर सहमति व्यक्त की। अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही यात्रियों की जान को जोखिम में डाल सकती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मानवाधिकार आयोग ने मांगी है रिपोर्ट

गौरतलब है कि देशभर में स्लीपर बसों में 20 से अधिक आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कई यात्रियों की जान चली गई। इन घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद से ही स्लीपर बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है।

फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य

अधिकारियों के अनुसार एआइएस तकनीकी सुरक्षा मानक के अंतर्गत बस की संरचना, विद्युत प्रणाली और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जांच की जाती है। विशेष रूप से एआइएस-119 मानक के तहत स्लीपर बसों में फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते चेतावनी मिल सके और बड़े हादसे को रोका जा सके।

Source: https://www.etvbharat.com/en/state/patna-shambhu-girls-hostel-student-death-case-suspicion-from-police-to-hospital-enn26012001733

Behind Mudslinging Over Death Of A Girl Preparing For NEET In Patna, Shadow Of Sexual Assault, Cover-Up?

The student's death at Shambhu Girls Hostel in Patna is getting more complicated, as phone records, CCTV footage, medical reports reveal conflicting information.

By ETV Bharat English Team

Published : January 20, 2026 at 2:18 PM IST

10 Min Read

By Brijam Pandey

Patna: The death of a girl student, who was preparing for the NEET medical entrance examination, at the Shambhu Girls' Hostel in Patna has put the entire state administration under scrutiny, after questions were raised over the hospital report and police statements. From ordinary citizens to politicians, everyone is outraged, with a steady trickle of revelations surfacing regularly on social media.

The Incident

The deceased, a resident of Jehanabad district, was staying at the hostel in Patna for NEET tuition classes. She had arrived from her home to the hostel in Patna on January 5, and was found unconscious in her room on January 6. She died on January 11 while undergoing treatment.

Initially, the police suspected a sleeping pill overdose, but the post-mortem revealed multiple injuries, scratches, and severe trauma to the private areas, raising the possibility of rape. The post-mortem further said the injury marks appeared to have been sustained during a struggle. The report further stated the student was menstruating, which could affect some aspects of the investigation, before foregrounding the “possibility of rape”. Following these revelations, the police have changed the direction of their probe. But they are yet to find any concrete evidence.

So, what exactly happened at the hostel on the night of January 5?

Three Theories Behind The Death

With three parallel theories, the police and the SIT (Special Investigation Team) have now converged on a single point, which in forensic terms is called the PO (Place of Occurrence), ie., the crime scene. There are many questions surrounding the death. Was it a suicide, or was there a larger conspiracy?

First Theory: Jehanabad is only 45 km from Patna. The police are thoroughly investigating the student's mental state when she arrived from Jehanabad. Did anything untoward happen to her during the journey? What happened on the way is yet to be revealed, but is deemed crucial to the probe.

Second Theory: Where did she go and whom did she meet after arriving in Patna and before going to the hostel? CCTV footage and mobile location data are being examined. However, CCTV footage has not yet been made public. The police have stated that in the hostel's CCTV footage, the student appeared "normal".

Third Theory: Did something wrong happen to the student at the hostel? The hostel owner has been arrested. According to latest reports, police have also detained three people for questioning. Will the SIT probe reveal what happened to the student from the night of the 5th to that of the 6th? Why was she found unconscious in her room?

A Timeline Of Events

January 6: According to the family, when the student was found unconscious under suspicious circumstances at the hostel, the hostel authorities immediately admitted her to a private hospital, though they were informed much later. When they reached Patna, the hostel authorities gave them conflicting accounts. The father alleges

that the hostel's CCTV footage was deliberately deleted "to prevent the truth from coming out". He also alleged that sleeping pills were placed in the room to make it look like a suicide.

Meanwhile, the victim's uncle alleged that the hostel owner tried to hush up the matter by offering money. The hospital doctor had also stated that the student's condition was critical, and that there were injury marks on her body and head. A relative of the victim said, "When she was admitted to Prabhat Memorial Hospital, her condition was critical. She was unable to speak and there was no movement in her body. A junior doctor at the hospital said he suspected foul play after seeing the injuries on her body and head."

January 11: After fighting for her life in hospital for 5 days, the student succumbed to her injuries during treatment. Her father filed a complaint at the Chitragupta Nagar police station, alleging murder and rape, based on which, a case was registered. The family alleged there were several injury marks on the student's body, which indicates she was subjected to violence.

In their preliminary statement, doctors at the hospital denied sexual assault, even though the police's stance was different. ASP (Sadar) Abhinav Kumar said even though they couldn't confirm sexual assault in their initial probe, they couldn't completely rule it out, which is why a videographed post-mortem was conducted at Patna Medical College Hospital (PMCH), after a medical board was formed.

Police also said the victim's January 8 urine report showed signs of an overdose of sleeping pills. Additionally, the mobile phone's search history showed searches related to the effects of sleeping pills and suicide on December 24 and January 5. This raises the suspicion that she was depressed. However, police have clarified that this is only one aspect of their probe, and that it would be premature to draw any conclusions.

"The scratches and injury marks found on the student's shoulder and other body parts are also under probe. The hostel owner, manager, and other staff have been questioned. The police will not act on emotions but on the basis of evidence," said Abhinav Kumar, ASP (Sadar).

January 12: After the victim passed away, outraged family members protested with her body at the city's Kargil Chowk. A large crowd gathered, raising tension, at which, the police erected barricades and deployed personnel from four more police stations — Gandhi Maidan, Kadamkuan, Jakkanpur, and Peerbahore — at the spot. When the situation worsened, they resorted to "mild force" to disperse the protesters.

Considering the family's protest and allegations, another medical board was formed at PMCH, and a fresh post-mortem conducted. But with the family not satisfied with the findings of this report, it was sent to AIIMS Delhi for further study. Although the initial report did mention "coercion", whether or not it constituted sexual harassment is still under investigation. The AIIMS Delhi report is expected to throw light on this.

January 15: Based on the post-mortem report, the police arrested the girls' hostel owner Manish Kumar on charges of negligence, and said that the possibility of rape could not be ruled out. They also said further action would be taken on the basis of the AIIMS Delhi report on the post-mortem, and other technical evidence.

January 16: Bihar Home Minister Samrat Chaudhary took cognisance and told the Bihar DGP to form a SIT, which includes City SP (East) Parichay Kumar, along with a female DSP, a female inspector, a male inspector, a sub-inspector, an ASI, and a constable.

January 17: ADG Amit Kumar Jain, Range IG Jitendra Rana, and the entire SIT team, including Patna SSP Kartikeya Sharma, inspected the hostel, collected evidence, and sealed the room. Sharma said according to police records, she had gone to her home in Jehanabad on December 26, and returned on January 5, and that CCTV footage from the station to the hostel does not show any incidence of sexual assault.

He said, "The camera outside the hostel room shows no signs of forced entry or coercion. It shows the warden coming over to ask her if she wanted to eat. The girl's movements appear normal. There is a video of the door being broken down after the incident. We are also awaiting forensic and AIIMS reports."

He also said they can show the CCTV recordings, phone records, doctor's reports, or any other evidence the family wants to see. But none of it can be made public, because it involves a minor under 18 years of age.

January 18: A Patna Police SIT reached the student's ancestral home in Jehanabad, stayed in the village for about four hours, and recorded statements from more than a dozen people, including family members. The family told them that the last cellphone conversation with the victim had taken place at 9 om on January 5.

January 19: Bihar Deputy CM and Home Minister Samrat Choudhary said they have formed an SIT, whose work is being monitored by the Patna IG, with the Bihar DGP overseeing the entire case. He added that the ADG had also reviewed the case and given the police a free hand.

Outrage, Protests, Political Reaction

Academicians React: The incident has sparked outrage among academics, politicians, and the general public. Alakh Pandey, the founder of edtech major Physics Wallah, raised several questions about it, demanding that the government and police take swift action.

He asked, "Why isn't the administration sensitive in cases involving girls? Why isn't action taken immediately, as soon as such cases come to light? Why was the SIT formed only after the public outcry?" adding, "Immediate action must be taken in such cases. Rules will have to be made so that our daughters are safe. Only then will the girls of the country progress, study, and get jobs."

Pandey further said in India, women's safety is only discussed in Parliament, while on the ground, it takes 10 days to form a SIT.

Civil Society Alerts Human Rights Commissions: Senior human rights advocate and Muzaffarpur resident S K Jha, who has filed separate petitions with the National Human Rights Commission (NHRC) and the State Human Rights Commission (SHRC) in the case, said, "Prima facie, this case points to a serious criminal act. At the initial stage, attempts were made to suppress the truth and portray it as a suicide."

He alleged that at any stage of the probe, negligence or attempt to conceal the truth constitutes a punishable offense, adding that in a civilised society, the safety of daughters should be the highest priority. He demanded a high-level probe supervised by a retired HRC judge, saying he has also sent letters to the chief justices of the Supreme Court and the Patna High Court.

Congress Protests: During a protest in Patna on Monday, Bihar Congress in-charge Krishna Allavaru said, "Such incidents are happening because the Bihar government has failed to provide security to our daughters." Congress leaders also raised slogans against the government.

RJD's Tejashwi Yadav Blames Government: Leader of the Opposition (LoP) in the Bihar Assembly, Tejashwi Yadav, also commented on the incident, saying that the corrupt and dysfunctional double-engine NDA government has become a tool for oppressors, corrupt individuals, criminals, and rapists. He added that the Nitish government in Bihar, "which came to power through vote-buying, is perpetrating atrocities against minor girls, female students, daughters, and women".

"Because these atrocities are being committed with the support of those in power, officials are remaining silent, pretending to be virtuous while doing nothing," said the RJD leader.

The RJD leader mentioned several such incidents to allege government complicity, including the gang rape and murder of a widow in Madhepura, the gang rape and murder of a 4-year-old minor girl in Khagaria, and this incident, alleging that the ruling party has enabled a subsequent cover-up, which "reveals the ruthlessness, cruelty, and inhumane nature of the government".

Ministers Respond: With the matter escalating fast, Rural Works Minister Ashok Choudhary jumped in to the government's defence, saying, "The opposition is creating an uproar by misleading people, as it is seeking "mileage". The police are investigating the matter. Have faith in our SSP, IG, SIT team and our government."

Agriculture Minister Ram Kripal Yadav said, "The Congress is finished. They are protesting to stay in the limelight."

Union Minister Jitan Ram Manjhi, who is from the state, said it is not yet clear if the girl had been raped, although the police report doesn't rule out the possibility. He added, "This is a heinous crime. A SIT has been formed. The CBI has taken over. Strict action will be taken against whoever is found guilty."

Why The 'Delay In Action'?

Regarding the delay in taking action, Manjhi said all investigations take time, adding, "If something is done in haste, an innocent person might be punished, which would raise further questions. If there are any problems, I will personally speak to the Union Home Ministry."

Source: https://english.mathrubhumi.com/amp/education/news/nhrc-internship-march-2026-osti-l9lcnrw6

NHRC announces Online Short Term Internship (OSTI) March 2026

Last Updated: 20 January 2026, 04:04 PM IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has invited applications for the Online Short Term Internship Programme (OSTI), March 2026, to be held from March 9 to 20, 2026.

NHRC, mandated to promote Human Rights literacy and awareness as per the Protection of Human Rights Act, regularly conducts Internship Programmes, with a view to spreading awareness among University students about the need for protection and promotion of Human Rights.

This is a full-time Internship Programme from 10 am to 5.30 pm (Monday to Friday) during the notified period. There will be about 40-45 sessions on various human rights issues to sensitise the interns. The OSTI will include following inputs (i) Address/ Interaction with Honble Chairperson and Members of NHRC and other domain Experts including senior Govt. of India Officials (ii) Group Project work on Human Right issues (iii) Book Review Activity (iv) Films on Human Rights concerning child and bonded labour issues, Anti Trafficking, Health including mental health and Education issues etc. (iv) Virtual Field Visit to Jail, Police Station & NGO/ Shelter Homes. In these virtual visits, the interns get to see the workings of these institutions and may get their related questions addressed.

All the student interns successfully completing the internship would receive a stipend of Rs. 2000/-. Certificate of participation will be awarded to the candidates on the basis of their punctuality, discipline, participation in online sessions; timely submission of Group Project Presentation & Project Reports, Book Reviews. It is mandatory for interns to attend all the sessions of the internship.

Eligibility: Students (i) in 3rd year and onwards of any integrated 5-year PG Course (ii) in 3rd / final year of a graduation course (iii) in any semester/ year of any post-graduate degree course (also applicable to the students in three year LL.B. programme) (iv) in any semester/ year of any post-graduate diploma course (v) who are research scholars in any stream can apply.

Students must have consistently attained a minimum of 60% marks in Class XII and all subsequent semesters in attended degree or diploma courses, including the presently pursued courses.

The student should not be more than 28 years old as of January 1, 2026.

Students who have attended earlier Internship Programmes organised by NHRC will not be eligible to apply.

The Notification of OSTI-March, 2026, is available at https://nhrc.nic.in/ (Activities link)

Application for OSTI-March, 2026 can be submitted online at https://nhrc.nic.in, latest by 18.00 hours on January 28, 2026.

A 250-word write-up on the topic ‘Statement of Purpose for joining NHRC Online Short Term Internship’ must be submitted by the applicants online, along with the application form, which will also serve as a basis of selection. Students who have research potential in the areas relating to human rights, as indicated in the write-up, will be preferred. The students may also include the details of co-curricular activities, Moot Courts, Internships, and research projects for strengthening their application.

Applicants should enclose self-attested scanned copies of mark-sheets from 10th standard onwards and mark-sheets of each year/ semester of graduation & of the course pursued presently, and a letter of recommendation (LOR) by the concerned HOD/ Dean/ Principal, which should be of a date subsequent to the date of uploading of

the advertisement and for the presently pursued course.
The Final List of Selected Interns will be displayed on the NHRC website.

Hindu, Mumbai, 21/01/2026
Page No: 4, Size: 28.63cm × 14.71cm

From 'flexible' to fearful: women gig workers hemmed in by new rules

Ashna Butani
NEW DELHI

Women gig workers employed on service platforms say the promise of "flexibility" is collapsing amid new rules, constant surveillance, and a growing sense of insecurity.

"I always used to think this job was good for me; I have covered my children's education because of it. But recent policy changes have left us mentally and physically exhausted," said Manisha (name changed), a Delhi-based Urban Company (UC) worker. Amid ongoing protests by gig workers' unions across the country, women providing spa, massage, beauty, home service, and cleaning work say they are battling their own set of challenges. What was promoted as a "flexible" way to earn has become increasingly rigid.

Ms. Manisha says the company has recently introduced mandatory "peak hour" requirements. Workers now receive requests during specific time blocks, 9 a.m. to 11 a.m. and 4 p.m. to 8 p.m., and cannot switch off the app during these hours without penalty. "Some of us are having to choose between work and dropping our children to school," she said.

'We're being watched'

Shanti (name changed), another UC worker based in Delhi, says that workers can face automatic ID blocks if they cancel more than three jobs in a month. She notes that "bundle booking", where customers book multiple services at once, means deeper discounts for clients but reduces workers' earnings.

Seema, GIPSWU president, said women workers across the gig economy face distinct vulnerabilities. ASHNA BUTANI

Even during off-hours, Ms. Shanti says she cannot escape the company's monitoring systems. When she turns off her location, her phone begins buzzing within seconds, prompting her to turn it back on. "We feel like we're being watched all the time. If anyone takes offline work, their IDs will instantly be blocked. I don't take offline work, so I'm not scared, but I don't want to be tracked 24x7," she said.

Ongoing struggle

The Gig and Platform Service Workers Union (GIPSWU), a women-led union, submitted memorandums to the UC management in Jaipur on January 7. Their demands include removing the peak-hour system, restrictive cancellation rules, and the bundle-booking model. The union also wrote to the National Human Rights Commission (NHRC) on January 12, seeking intervention on ID blocking and bundle-booking practices. *The Hindu* contacted UC with detailed queries but did not receive a response till the time of going to press. Around 150-200 workers in Jaipur have kept their apps switched off since January 8. The union says workers across India will follow suit on January 26 and February 3 as a sign of protest.

Seema, a former UC worker and now GIPSWU president, said women workers across the gig economy, whether with UC, Amazon, or Flipkart, face distinct vulnerabilities. "Male clients sometimes book services pretending to be female. And when women are on long shifts during their period, there are no toilets," she said.

Blocked IDs

Ms. Manisha says any minor disagreement with a customer can trigger a strike. "We have to agree with clients, no matter how they treat us. Otherwise, we are the ones who suffer," she said. Ms. Shanti recalls being expected to travel from central Delhi to Greater Noida in just 15 minutes. When she took leave for a family wedding, the first in years, she received no job requests for days, which she believes was a form of punishment. Neha (name changed), a former worker whose ID was blocked after she attended protests in 2023, has been off the app for four years. "Earlier, we thought flexible work was a big benefit. Now, with constant surveillance and pressure, I never want to go back," she said.

Source: https://hindi.news18.com/news/nation/supreme-court-hears-stray-dogs-case-live-updates-sc-justices-vikram-nath-sandeep-mehta-and-nv-anjaria-10088524.html

Stray Dogs Case Highlights: एक पागल कुत्ते की वजह से सभी को सजा नहीं, दूसरे एडवोकेट बोले- हिंसक हैं तो उन्हें मारना अनिवार्य, कोर्टरूम में जोरदार बहस

Reported by: शंकर आनंद
Written by: अरुण बिंजोला
Agency:News18India
Last Updated:January 20, 2026, 17:41 IST

supreme court hearing on stray dogs live: सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चल रही पांचवें दिन की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने संस्थानों में कुत्तों की मौजूदगी और नगर निकायों की विफलता पर चिंता जताई, जबकि कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ने या रिहायशी सोसाइटियों से हटाने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस देखने को मिली.

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के प्रबंधन और इससे जुड़े जनहित से जुड़े अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही सुनवाई के तहत पांचवें दिन की कार्यवाही पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस चरण में याचिकाकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की दलीलें पूरी कर ली गई हैं. शीर्ष अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे तय की है, जिसमें राज्य सरकारों, एमिकस क्यूरी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पक्ष सुने जाएंगे.

Supreme Court Hearing Highlights:

– एक वकील ने कहा कि नगर पालिका अधिकारी समय पर कूड़ा नहीं उठाते, इसलिए कुत्ते जमा हो जाते हैं. शहरीकरण के कारण कूड़ा बढ़ गया है. मैंने कई FIR दर्ज कराई हैं, जिनमें कुत्तों को इंसानों ने पीट-पीटकर मार डाला. एक पागल कुत्ते की वजह से सभी कुत्तों को सज़ा नहीं दी जा सकती. एक अन्य वकील ने कहा कि मेरे पास छात्र-संचालित पशु कल्याण संस्था का एक बयान है. CSVR सिद्धांत के कारण आवारा कुत्तों की संख्या कम हुई है. पिछले 5 वर्षों से कुत्ते के काटने की कोई घटना नहीं हुई है. संख्या घट गई है, ABC केंद्र अंडाशय निकालते हैं और गिनती करते हैं और दूसरे आश्रय में भेज देते हैं. बिलिंग चलती रहती है, कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता. गिनती के तुरंत बाद अंडाशय नष्ट कर दिए जाने चाहिए. डेटा ऑनलाइन डाला जाना चाहिए, ताकि निगरानी हो सके.

संबंधित खबरें

– कुत्तों के काटने के शिकार होने वालों की ओर से SCBA के सदस्य व वकील शुभम गुप्ता ने कहा कि बार-बार काटने वाले आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है. भैंस आदि का इस्तेमाल भी इंसानों के खाने के लिए किया जाता है अगर कुत्ते आक्रामक और हिंसक हैं तो उन्हें मारना अनिवार्य है.

– जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि चूंकि आपकी मुवक्किल मंत्री रह चुकी हैं और पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं, तो हमें बताइए कि आपके आवेदन में बजट आवंटन का जिक्र क्यों नहीं है? इन क्षेत्रों में आपके मुवक्किल का क्या योगदान रहा है?

– रामचंद्रन ने कहा कि मैं इसका मौखिक उत्तर नहीं दे सकता. एक अन्य वकील ने कहा कि हर शहर में हेल्पलाइन होनी चाहिए. कुत्तों को मारना जायज नहीं है, इस अदालत के फैसले के बाद HC इस मामले को देखें.

– वकील अजीत शर्मा ने कहा कि नसबंदी आदि की जिम्मेदारी अधिकारियों की है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मद्देनजर इसे अन्य संस्थानों के साथ साझा किया जा सकता है. पर्यावरण में अन्य जीव और उनके आपसी संबंध भी शामिल हैं. अधिनियम समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और एसईआईए प्रतिदिन नए पर्यावरण स्वीकृतियां जारी करता है. इन स्वीकृतियों में कई शर्तें लगाई जाती हैं. इनमें एक शर्त यह जोड़ी जा सकती है कि संसाधन संपन्न संगठन नसबंदी आदि में संसाधन लगाएं.

– वकील राहुल कौशिक कुछ समाधान पर दलीलें दी और कहा कि हमारा बेंगलुरु नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन है. आरडब्ल्यूए को भोजन के लिए पर्याप्त जगह मिल सकती है. टीकाकरण के लिए एक उप-समिति बनाई जा सकती है. कुत्ते के काटने के कारण क्रूरता, स्थानांतरण, भोजन की कमी और उपचार का अभाव हैं. कुत्ते प्रेमियों को उचित स्थान मिल सकता है. तेलंगाना में पिछले सप्ताह 500 कुत्तों को मार दिया गया. सलाहकार बोर्ड बनाए जा सकते हैं. डॉग पाउंड भी कुत्ते के मांस की बिक्री का कारण बन रहे हैं.

– वकील राजू रामचंद्रन ने समस्या के समाधान के लिए सुझाव दिए. कहा- एबीसी नियमों का कार्यान्वयन समग्र रणनीति का अभिन्न अंग है. एनएपीआरई नीति ने रेबीज उन्मूलन में 9 बाधाओं की पहचान की है. इसमें सभी हितधारकों की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई गई है और राज्यों को अपनी कार्य योजनाएं विकसित करने का निर्देश दिया गया है. कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया है. समाधान स्थायी आश्रय स्थल बनाने में नहीं, बल्कि मौजूदा ढांचे के समयबद्ध कार्यान्वयन में निहित है.

– वकील प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि कुत्तों का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है. जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि हम कुत्ते को प्रमाण पत्र ले जाने के लिए क्यों नहीं कह सकते?

– वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि सुनवाई के दौरान जजों ने कुछ टिप्पणियां की हैं, जिनमें से कुछ का गलत अर्थ निकाला गया है. जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि कोई बात नहीं, तर्क अव्यावहारिक हैं.

– वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कभी-कभी कोर्ट की टिप्पणियों के गंभीर परिणाम हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए पीठ ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की कि दाना चुगली करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि नहीं-नहीं, बिल्कुल भी व्यंग्यपूर्ण नहीं था. हम गंभीर थे, हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम गंभीर थे.

– वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि बार के सदस्य के रूप में मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूं. कार्यवाही का टेलीविजन पर प्रसारण होता है. बार और पीठ दोनों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि हम जानते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हम ऐसा करने से बच रहे हैं.

– वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि प्रभावी नसबंदी कुछ शहरों में कारगर साबित हुई है. दुर्भाग्य से यह प्रणाली अधिकांश शहरों में कारगर नहीं रही है. नसबंदी से समय के साथ आवारा कुत्तों की संख्या कम हो जाती है, इससे उनकी आक्रामकता भी कम होती है. इसे प्रभावी कैसे बनाया जाए? इसे पारदर्शी बनाएं और लोगों को जवाबदेह बनाएं. एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां लोग बिना नसबंदी वाले आवारा कुत्तों की रिपोर्ट कर सकें. शिकायत पर कार्रवाई के लिए नामित अधिकारी होने चाहिए और उन्हें आकर जांच करनी चाहिए और स्थिति का जायजा लेना चाहिए.

– याचिकाकर्ता भारती त्यागी के वकील ने कहा कि मैंने इस मुद्दे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्याय क्षेत्रों द्वारा अपनाए जा रहे उपायों पर एक नोट दिया है. नीदरलैंड इसका एक सफल उदाहरण है. जानवरों को छोड़ने से रोकने के लिए नीदरलैंड का मॉडल अपनाया गया है. सुझाव: दंड सहित सख्त पशु क्रूरता-विरोधी कानून और अनिवार्य माइक्रोचिपिंग और एक केंद्रीय समन्वित कार्यक्रम होना जरूरी है. वकील हर्ष जैदका ने कहा कि मेरी चिंता अलग है. मेरे इलाके में बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, मुझे पूरी तरह से अशांति है. नींद की समस्या होने लगी है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि हम केवल टीकाकरण और नसबंदी कर सकते हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है और उपद्रव होने पर आवारा कुत्तों को हटाया जा सकता है.

– सुनवाई के दौरान एक वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी की ओर से मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पास इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम आंकड़े हैं. इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि हमें एक नोट दीजिए. पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि आज निजी पक्ष की दलीलें पूरी की जाएंगी और इसके बाद राज्य सरकारों को अपनी बात रखने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा.

– सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर देशभर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका सीधा असर आवारा कुत्तों के प्रबंधन, नगर निकायों की जिम्मेदारी और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े नीतिगत फैसलों पर पड़ सकता है.

– पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक परिसरों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताई थी. साथ ही नगर निकायों की भूमिका और उनकी विफलता को लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह सिर्फ पशु कल्याण का नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है.

Dainik Bhaskar, Online News, 21/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/amp/local/bihar/patna/news/neet-students-death-only-fsl-and-aiims-reports-will-reveal-the-truth-137000815.html

नीट छात्रा की मौत : एफएसएल और एम्स की रिपोर्ट ही बताएगी असलियत

पटना 4 घंटे पहले

नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी को पटना एम्स के ओपिनियन और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी की जांच में अबतक उसके साथ पटना के हॉस्टल या कहीं भी घिनौनी हरकत के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस के पास छात्रा के पटना आने से लेकर अस्पताल तक एडमिट होने तक का सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि परिजनों का दावा है कि उसके साथ हॉस्टल में घिनौनी हरकत के बाद हत्या कर दी गई। एसआईटी की जांच का फोकस जहानाबाद हो गया है।

इस हालांकि मंगलवार को भी मुन्नाचक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एसआईटी पहुंची थी। इसी हॉस्टल में रह कर छात्रा नीट की तैयारी कर ही थी। एसआईटी ने ग्राउंड से पांचवें फ्लोर तक चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। उधर, वकील डॉ. कौशलेंद्र नारायण ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज केस कराई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने भी डीएम को पत्र लिखकर पटना में चल रहे निबंधित गर्ल्स हॉस्टल और उनमें सुविधाओं की जानकारी मांगी है।

हॉस्टल के बाहर रोज लगी रहती थी एक सफेद रंग की कार, एक बुलेट

उधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि हॉस्टल के ऊपर कुछ युवक भी रहते थे। हॉस्टल के बाहर एक उजले रंग की कार और एक बुलेट प्रतिदिन लगी रहती थी। देर रात दोनों गाड़ियां वहां से चली जाती थीं। पुलिस कार और बुलेट मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है कि जब वह पटना से 26 दिसंबर को जहानाबाद पहुंची तो उसकी क्या हालत थी? वह किस-किस से मिली। एसआईटी ने उसके डायरी को भी एफएसएल भेजा है कि यह उसकी राइटिंग है या नहीं?

एम्स से 25 प्वाइंट पर मांगी रिपोर्ट

अधिवक्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च

पटना अधिवक्ता संघ ने इस घटना के विरोध में मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च जिला बार संघ से अशोक राजपथ पर स्थित कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स तक गया। सैकड़ों अधिवक्ता मार्च में शामिल हुए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिन्हा ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मार्च में महासचिव अरविंद कुमार महुआर, श्यामल प्रसाद, अमरेंद्र कुमार, अंशुमान आदि शामिल थे।

पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तीन अस्पतालों का ट्रीटमेंट चार्ट पटना एम्स भेजा गया है। पटना एम्स ने सेकंड ओपिनियन देने के लिए 5 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया है। एसआईटी ने इनसे 25 प्वाइंट पर ओपिनियन मांगे हैं। मौत की क्या वजह थी? उसके साथ घिनौनी हरकत हुई या नहीं? पीएमसीएच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं नहीं किया जा सकता है, इसपर एम्स का ओपिनियन क्या है? उसके शरीर पर किस तरह के निशान हैं? नाखून के निशान किसी दूसरे के हैं? वहीं एफएसएल से रिपोर्ट मांगी गई है कि छात्रा के कपड़े पर किसी अन्य के कोई साक्ष्य हैं या नहीं? क्या उसकी मौत नींद की गोली खाने से हुई?

Source: https://idtvindradhanush.com/latest-news/supreme-court-angry-over-stray-dog-menace-questions/?amp=1

Supreme Court on stray dogs: आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, नगर निकायों के साथ डॉग फीडर्स की भूमिका पर उठाए सवाल

Last updated: जनवरी 20, 2026 6:39 अपराह्न
By Juli Gupta
3 Min Read

नई दिल्ली, एजेंसियां। आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि किसी हमले में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आती है या उसकी मौत होती है, तो केवल नगर निकाय ही नहीं, बल्कि डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट कहा कि उसकी पिछली टिप्पणियों को मजाक या व्यंग्य समझना गलत होगा, अदालत इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

पीठ ने कहा

पीठ ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है और कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगी। अदालत ने संकेत दिया कि निजी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें एमिकस क्यूरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के वकील और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की दलीलें सुनी जाएंगी।

कोर्ट में तीखी बहस, दोनों पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से कहा गया कि आवारा कुत्तों के हमलों से खासकर बच्चों और आम नागरिकों की जान खतरे में है और प्रशासन समय पर प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा है। कुछ वकीलों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ऐसी मौतों के लिए राज्य सरकार मुआवजे की जिम्मेदार होनी चाहिए।

वहीं, डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि समस्या का समाधान कुत्तों को मारना नहीं, बल्कि प्रभावी नसबंदी, टीकाकरण और कचरा प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश देता है और वैज्ञानिक तरीकों से ही इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

रेबीज और इलाज पर भी चिंता

सुनवाई के दौरान रेबीज की रोकथाम और इलाज को लेकर भी सवाल उठे। अदालत ने माना कि रेबीज पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है, लेकिन भारत में प्रभावी नीति की कमी है। कोर्ट ने दोहराया कि वह संतुलन और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत के साथ इस संवेदनशील मुद्दे पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी।

Source: https://theprint.in/theprint-essential/nata-vivah-contractual-marriage-rajasthan-high-court/2831632/?amp

What is Nata Vivah? Contractual marriage recognised by Rajasthan High Court

The practice has long been viewed as a means of misuse and exploitation of women, as it does not grant them legal rights or formal family recognition.

Almina Khatoon 20 January, 2026 01:28 pm IST

New Delhi: The Rajasthan High Court on 16 January recognised Nata Vivah and granted a woman the right to receive a family pension after the death of her husband.

Nata Vivah is a traditional, agreement-based form of marriage practised in certain communities in Rajasthan. In the present case, 60-year-old Ram Pyari Suman filed a petition before the High Court after the concerned government department her husband Pooran Lal Saini was employed with refused to grant her the pension. The department rejected Suman's claim on the grounds that she was recorded only as a "Nata wife" in government records and was not nominated as a family member.

Suman's counsel, Tushar Panwar, informed the court that after the death of Saini's first wife, Saini entered into a Nata Vivah with Suman approximately 20 years ago, and the couple has a daughter.

However, due to subsequent domestic disputes, Suman applied for maintenance. During those proceedings, Saini acknowledged before the family court that Suman was his wife and accepted responsibility for providing maintenance to her and her daughter.

Following Saini's death, Suman demanded that the state government release the family pension. However, the officials denied her request.

A single bench of Justice Ashok Kumar Jain directed the state authorities to release the pension under the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, recognising Suman as the legal wife of the deceased.

"It is necessary for the Court to consider Nata Vivah. It is a practice prevalent in some rural areas of Rajasthan where, after the death of or separation from an existing husband, a woman enters into a contractual type of marital relationship with a man. Thus, there is no dispute that Nata Vivah is also considered a form of marriage in rural areas of Rajasthan," the court observed.

What is Nata Vivah?

Nata Vivah, also known as Nata Pratha, is a traditional, non-formalised custom of remarriage or cohabitation followed in rural and tribal areas of Rajasthan. It is also prevalent in some parts of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat.

Nata Vivah is not recognised under the traditional form of Hindu marriage, as it is based solely on community consent. It emerged as a customary arrangement for widows, divorced women, and abandoned women, providing them with a means to enter into a new relationship with social acceptance.

However, the practice has long been viewed as a means of misuse and exploitation of women, as it does not grant them legal rights or formal family recognition. The National Human Rights Commission (NHRC) and several non-governmental organisations working for women's rights have urged the government to make the registration of customary marriages such as Nata Vivah mandatory.

In 2024, the NHRC took serious note of Nata Pratha, under which girls in some communities are reportedly sold—often through agreements on stamp paper or informal contracts—in the name of marriage, despite the practice having no legal sanctity. The NHRC also highlighted the misuse of this tradition, including instances of minors being married to older men.

In the past, the statutory body has called for the complete eradication and abolition of the practice and issued

notices to the Union Ministry of Women and Child Development and the respective state governments.

The problem

Women in Nata Vivah arrangements are often viewed as secondary or temporary wives.

However, in the case of Ram Pyari Suman v. the State of Rajasthan, the court noted that when Nata Vivah is conducted with customary ceremonies and in accordance with the rights and traditions of the parties' community, it can be recognised under law pursuant to Section 7 of the Hindu Marriage Act.

The court ruled that a woman in a Nata relationship is entitled to her husband's family pension, even if her name does not appear in the official service records. Based on the family court's 2017 order, the court recognised Suman as the legal wife and directed that her pension be released.

(Edited by Prasanna Bachchhav)

Source: https://www.jansatta.com/national/nhrc-helps-bihar-boy-who-was-forced-into-bonded-labour/4367853/

स्टेशन पर पिता से बिछड़े नाबालिग से शख्स ने कराई बंधुआ मजदूरी, हाथ कटा तो जंगल में छोड़ भागा; दिल दहला देगी दास्तां

Richa Sahay | January 20, 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हाल ही में बिहार के किशनगंज के एक नाबालिग लड़के के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसे हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर उसके पिता से बिछड़ जाने के बाद बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था। खबरों के मुताबिक, लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा लेकिन भारी भीड़ के कारण अपने पिता के पास वापस जाने के लिए ट्रेन में नहीं चढ़ सका। जिसके कारण उसकी ट्रेन छूट गई और आठ महीने तक लड़के को बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। NHRC ने पाया कि उसका बायां हाथ कटा हुआ था।

आयोग ने अगस्त 2025 में द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और निकाय के अन्य सदस्यों ने जनवरी 2026 में पाया कि आरोपी अनिल कुमार (28) ने 16 साल के नाबालिग लड़के को बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अकेला पाया था। जिसके बाद आरोपी ने उसे कैद कर रख लिया और उसे अपनी डेयरी में काम करने के लिए मजबूर किया।

आरोपी ने लड़के से कराई बंधुआ मजदूरी

आयोग के समक्ष रखी गई पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अनिल कुमार ने स्वीकार किया था कि उसने मई 2025 की रात में बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर लड़के को रोते हुए देखा था। बाद में उसे पता चला कि लड़का अपने परिवार से अलग हो गया था और उसके पास न तो टिकट था और न ही पैसे। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसने लड़के को अपनी डेयरी में काम पर रखने का फैसला किया और स्थिति का फायदा उठाते हुए, लड़के को अपनी बाइक पर डेयरी में ले आया और उसे पशुओं के काम में लगा दिया।

मशीन से चारा काटते समय कटा नाबालिग का हाथ

अभियुक्त ने आगे बताया कि नाबालिग को दिन के समय जंगल में भैंस चराने के लिए मजबूर किया जाता था। आरोपी ने नाबालिग को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी और उस पर कड़ी निगरानी रखी। एक बार लड़के ने भागने की कोशिश की पर अनिल ने उसे पकड़ लिया। लगभग दो महीने बाद, जब लड़का मशीन से चारा काट रहा था तो उसका बायां हाथ मशीन में फंस गया और कोहनी तक कट गया।

आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने चारे के साथ लड़के के कटे हुए हाथों के टुकड़ों को भी अपने घर से दूर यमुना नदी में फेंक दिया था। अनिल ने यह भी स्वीकार किया कि उसने लड़के को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया और केवल घर पर कुछ दवाइयाँ दीं। हालांकि, चोट बहुत गंभीर होने के कारण नाबालिग ठीक नहीं हो सका। इसके बाद, आरोपी ने पुलिस के डर से लड़के को छोड़ने का फैसला किया और उसे हरियाणा के पास एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। आरोपी ने लड़के को बाद में और पैसे देने के वादे के साथ 10,000 रुपये दिए थे।

NHRC ने लिया मामले का संज्ञान

मामले पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और बिहार के किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए। एनएचआरसी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे सूचित करें कि क्या पीड़ित को कोई मुआवजा दिया गया है। साथ ही उसे विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं ताकि पीड़ित विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के लाभ प्राप्त कर सके। इस घटनाक्रम में, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की जांच की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उस अपराधी का पता लगाने के लिए ईमानदार प्रयास किए।

Source: https://www.deccanherald.com/india/contempt-of-court-supreme-court-irked-by-maneka-gandhis-criticism-of-its-order-in-stray-dog-case-3868369

'Contempt of court': SC slams Maneka Gandhi for criticising order in stray dog case

The top court orally said that she has "committed contempt of court," but it was the court's "magnanimity" that it did not take contempt action against her.

Ashish Tripathi DHNS Last Updated : 20 January 2026, 15:53 IST

New Delhi: The Supreme Court on Tuesday came down heavily on former Union minister and animal rights activist, Maneka Gandhi for her remarks criticising the apex court's orders in the stray dog issue.

The top court orally said that she has "committed contempt of court," but it was the court's "magnanimity" that it did not take contempt action against her. Taking up a suo motu case related to stray dogs, a bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and N V Anjaria took strong exception to Gandhi's statements during a podcast.

The court asked senior advocate Raju Ramachandran, appearing for Gandhi, "You were telling the court we should be circumspect, but what kind of statements she was making?"

"Your client has committed contempt. We are not taking cognisance of that. That is our magnanimity. Have you heard her podcast? What is her body language? What she says and how she says," the bench said.

The bench also said as a former minister, she has made "all kinds of comments against everyone without even thinking."

During the hearing at one point, Ramachandran said, he had appeared for 26/11 terrorist Ajmal Kasab. Hearing this, Justice Nath replied, "Kasab had not committed contempt." The submissions of individuals, NGOs concluded on Tuesday. The court fixed the matter for further hearing on January 28.

Advocate Prashant Bhushan, appearing for one of the petitioners, said sterilisation reduces the aggression of stray dogs, but no effective sterilisation is being implemented in most cities.

He argued that the court's observations can sometimes lead to unfortunate consequences. "For example, the said feeders should be made responsible for dog bites. Perhaps it was sarcastic," he added.

The bench, however, replied, "No, we didn't make it sarcastically. We said it very seriously." Advocate Harsh Jaidka, for another petitioner, said, there were many stray dogs where he stayed and there was much disturbance. "I have started having sleep disorder. Kids can't study. Authorities did not initiate any action. They said we can only do vaccination and sterilisation.

NHRC has also not taken any action. In case of nuisance, stray dogs can be removed," he submitted. Another lawyer contented that there should be a helpline in every city. Senior advocate Siddharth Dave, said, "Constitution mandates us to be compassionate towards all beings." Another advocate, Ajit Sharma, contended that responsibility to sterilise rests on authorities.

Source: https://www.thehansindia.com/amp/news/national/womens-commission-takes-suo-motu-cognisance-of-neet-students-death-in-patna-1040667

Women's Commission takes suo motu cognisance of NEET student's death in Patna

The Hans India | Update: 2026-01-20 06:21 IST

Patna: The Bihar State Women's Commission has taken suo motu cognisance of the suspicious death of a NEET aspirant in Patna.

Chairperson Prof. Apsara will visit Jehanabad on Wednesday, January 21, to meet the family of the deceased and assess the situation on the ground.

Prof. Apsara has written to the Senior Superintendent of Police (SSP) in Patna, demanding immediate action against the culprits and seeking a detailed investigation report to be submitted to the Commission.

She stated that the Commission is closely monitoring the case and assured that no guilty person will be spared.

Following the Commission's intervention, the hostel operator has been arrested, and a Special Investigation Team (SIT) has been constituted to probe the case.

The deceased, a resident of Jehanabad district, was preparing for the NEET examination while staying at a hostel in Patna.

She died under suspicious circumstances, triggering statewide outrage and protests by students and social organisations.

Providing a major update, ADG (CID) Parasnath said that it would be premature to disclose details until the investigation is completed.

"This entire matter is under investigation. It would not be appropriate to make any detailed information public at this stage," the ADG said while addressing the media.

He explained that technical and scientific investigations take time, particularly DNA analysis.

"Most of the testing process is expected to be completed within the next three to four days. DNA reports may take five to six days, depending on available resources," he said.

When asked about the exact date of the student's admission to Prabhat Memorial Hospital, the ADG said that he did not have confirmed information at the moment, but assured that every aspect is being thoroughly investigated.

The Forensic Science Laboratory (FSL) has conducted an extensive investigation at the hostel where the student lived.

The FSL team collected crucial evidence from the scene that could help establish the truth.

The case has sparked a political storm, with opposition parties accusing the government of administrative failure and delayed action.

Student organisations and social groups have intensified protests, demanding swift justice for the victim.

Times of India, Delhi, 21/01/2026
Page No: 10, Size: 15.88cm × 42.55cm

NHRC notices to states after bonded labourer loses arm

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the case of a boy who was kept as bonded labour for months after being separated from his father at Bahadurgarh railway station in Haryana. The commission has issued notices seeking a response on the matter from the authorities in Haryana, UP and Bihar.

Taking cognisance of a media report, NHRC noted in a statement that "reportedly, the boy stepped off the train to fetch water at the railway station but could not board it again to be with his father due to the heavy crowd. Thereafter, he missed the train and for eight months suffered the ordeal of bonded labour before managing to reach his home with his left elbow severed."

The commission's statement dated Jan 15 added, "The news report has also revealed that a bonded labour release certificate, which is a mandatory document required to access any rehabilitation and compensation for the victim, is yet to be released by the authorities, under Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer-2021."

The commission has issued notices to the chief secretary and director general of police, Haryana, as well as commissioner of police, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh and district magistrate, Kishanganj, Bihar, seeking a response within two weeks.

The authorities have also been directed to reveal whether any compensation has been paid and a disability certificate issued to enable the victim to get the benefits of the Persons with Disabilities (PwD) Act, 2016.

According to the media report dated Jan 12, after missing the train, the boy stayed at the railway station for two days, following which a man, in the name of providing him a job, took him to Greater Noida area in Gautam Buddha Nagar district of Uttar Pradesh, where he was made to work from early morning until night and allegedly subjected to frequent physical torture by his employer.

The victim reportedly made an unsuccessful attempt to escape from bondage, but he was caught and subject to beatings. The news report further revealed that the victim's arm got severed at the elbow in a fodder cutting machine. He was then abandoned on a road by his employer without being provided any medical aid.

Reportedly, an unknown person took him to a hospital in Nuh district of Haryana, from where, out of fear of again being caught by his employer, he ran away and walked barefoot for more than three km until two govt teachers noticed him, and the matter was reported to the GRP, Bahadurgarh, Haryana. He finally returned home in Aug 2025.

Source: https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/from-flexible-to-fearful-women-gig-workers-hemmed-in-by-new-rules/article70530973.ece

From ‘flexible’ to fearful: women gig workers hemmed in by new rules

Updated - January 21, 2026 01:52 am IST - NEW DELHI
Ashna Butani
Women gig workers employed on service platforms say the promise of “flexibility” is collapsing amid new rules, constant surveillance, and a growing sense of insecurity.
“I always used to think this job was good for me; I have covered my children’s education because of it. But recent policy changes have left us mentally and physically exhausted,” said Manisha (name changed), a Delhi-based Urban Company (UC) worker. Amid ongoing protests by gig workers’ unions across the country, women providing spa, massage, beauty, home service, and cleaning work say they are battling their own set of challenges. What was promoted as a “flexible” way to earn has become increasingly rigid.
Ms. Manisha says the company has recently introduced mandatory “peak hour” requirements. Workers now receive requests during specific time blocks, 9 a.m. to 11 a.m. and 4 p.m. to 8 p.m., and cannot switch off the app during these hours without penalty. “Some of us are having to choose between work and dropping our children to school,” she said.
‘We’re being watched’
Shanti (name changed), another UC worker based in Delhi, says that workers can face automatic ID blocks if they cancel more than three jobs in a month. She notes that “bundle booking”, where customers book multiple services at once, means deeper discounts for clients but reduces workers’ earnings. Even during off-hours, Ms. Shanti says she cannot escape the company’s monitoring systems. When she turns off her location, her phone begins buzzing within seconds, prompting her to turn it back on. “We feel like we’re being watched all the time. If anyone takes offline work, their IDs will instantly be blocked. I don’t take offline work, so I’m not scared, but I don’t want to be tracked 24x7,” she said.
Ongoing struggle
The Gig and Platform Service Workers Union (GIPSWU), a women-led union, submitted memorandums to the UC management in Jaipur on January 7. Their demands include removing the peak-hour system, restrictive cancellation rules, and the bundle-booking model. The union also wrote to the National Human Rights Commission (NHRC) on January 12, seeking intervention on ID blocking and bundle-booking practices. The Hindu contacted UC with detailed queries but did not receive a response till the time of going to press. Around 150-200 workers in Jaipur have kept their apps switched off since January 8. The union says workers across India will follow suit on January 26 and February 3 as a sign of protest.
Seema, a former UC worker and now GIPSWU president, said women workers across the gig economy, whether with UC, Amazon, or Flipkart, face distinct vulnerabilities. “Male clients sometimes book services pretending to be female. And when women are on long shifts during their period, there are no toilets,” she said.
Ms. Manisha says any minor disagreement with a customer can trigger a strike. “We have to agree with clients, no matter how they treat us. Otherwise, we are the ones who suffer,” she said. Ms. Shanti recalls being expected to travel from central Delhi to Greater Noida in just 15 minutes. When she took leave for a family wedding, the first in years, she received no job requests for days, which she believes was a form of punishment. Neha (name changed), a former worker whose ID was blocked after she attended protests in 2023, has been off the app for

four years. “Earlier, we thought flexible work was a big benefit. Now, with constant surveillance and pressure, I never want to go back,” she said.

Dainik Bhaskar, Online News, 21/01/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/yachikakarta-ke-sujhav-par-supreme-court-ki-sakht-tippani-hum-kutton-se-certificate-lekar-chalne-ko-kyon-nahin-kah-sakte-1241766

याचिकाकर्ता के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, हम कुत्तों से सर्टिफिकेट लेकर चलने को क्यों नहीं कह सकते

20 Jan 2026 4:00 PM

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लावारिस कुत्तों के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके इलाके में बहुत सारे लावारिस कुत्ते हैं, जो पूरी रात एक-दूसरे का पीछा करते रहते हैं, भौंकते हैं, जिससे उन्हें नींद नहीं आती और उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते।

नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लावारिस कुत्तों के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके इलाके में बहुत सारे लावारिस कुत्ते हैं, जो पूरी रात एक-दूसरे का पीछा करते रहते हैं, भौंकते हैं, जिससे उन्हें नींद नहीं आती और उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। याचिकाकर्ता ने इस मामले में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनका कहना कि वे केवल वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। एनएचआरसी को भी भी पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स (एबीसी नियम) केवल एक खास दायरे में काम करते हैं। कुत्तों को स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन के बाद फिर से छोड़ दिया जाता है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि दुनियाभर में यह स्वीकार किया जाता है कि लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी नसबंदी व्यवस्था जरूरी है। जयपुर और गोवा जैसी जगहों में यह सिस्टम सफल रहा है, लेकिन ज्यादातर शहरों में स्टरलाइजेशन प्रभावी नहीं हो पा रहा। स्टरलाइजेशन से कुत्तों की आक्रामकता कम होती है, लेकिन समस्या यह है कि कई शहरों में सही ढंग से यह नहीं हो रहा। इसे बेहतर बनाने के लिए पारदर्शिता लानी होगी और लोगों को जवाबदेह बनाना होगा। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां लोग उन लावारिस कुत्तों की रिपोर्ट कर सकें जिनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है। इसे किसी वेबसाइट पर दर्ज किया जाए और कोई विशेष अथॉरिटी हो जो ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करे।

प्रशांत भूषण के इस सुझाव पर जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि हम कुत्तों से खुद सर्टिफिकेट लेकर चलने को क्यों नहीं कह सकते। प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत संदेश दे सकती हैं। उदाहरण के लिए इसी कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों के काटने के लिए फीडर्स को जिम्मेदार ठहराया जाए, जो शायद व्यंग्य था। जस्टिस विक्रम नाथ ने स्पष्ट किया कि यह व्यंग्य में नहीं कहा गया था, बल्कि बहुत गंभीरता से कहा गया था।

इसके अलावा, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मामले पर किए गए पॉडकास्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूर्व मंत्री की तरफ से पेश हुए वकील राजू रामचंद्रन से कहा कि थोड़ी देर पहले आप कोर्ट से टिप्पणियों को लेकर सावधान रहने की बात कर रहे थे। क्या आपको पता है कि आपके क्लाइंट किस तरह की बातें कर रही हैं? आपके क्लाइंट ने कोर्ट की अवमानना की है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, यह हमारी दरियादिली है। क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? वह क्या कहती हैं और कैसे कहती हैं। आपने टिप्पणी की कि कोर्ट को सावधान रहना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर आपकी क्लाइंट जिसे चाहे और जिसके बारे में चाहे, हर तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मानव सुरक्षा, एबीसी नियमों के क्रियान्वयन और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर विचार कर रहा है। सुनवाई आगे जारी रहेगी।

Source: https://mpcg.ndtv.in/madhya-pradesh-news/sagar-kinnar-controversy-national-human-rights-commission-takes-action-sends-notice-to-sagar-tikamgarh-sp-10792616

Kinnar Controversy: सागर किन्नर विवाद मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक्शन, सागर-टीकमगढ़ SP को भेजा नोटिस

Sagar Kinnar Controversy: किन्नर रानी ठाकुर ने सागर की किन्नर किरण नायक पर गंभीर आरोप लगाए थे. रानी ठाकुर का दावा किया था कि सागर के रंग महल में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया है, जहां रहने वाले सभी किन्नरों पर नमाज पढ़ने और रोजा रखने का दबाव बनाया जाता है.

Written by:हनी दुबे
Edited by:Priya Sharma

मध्य प्रदेश न्यूज़
जनवरी 20, 2026 17:46 pm IST
Published Onजनवरी 20, 2026 17:46 pm IST
Last Updated Onजनवरी 20, 2026 17:46 pm IST

सागर जिले से जुड़े चर्चित 'किन्नर विवाद' मामले में अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने सागर पुलिस अधीक्षक और टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आयोग ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा है.

मोना ने टीकमगढ़ में की थी आत्महत्या

आयोग द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बीते दिनों सागर की रहने वाली किन्नर मोना ने टीकमगढ़ में आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद मृतक मोना की गुरु किन्नर रानी ठाकुर ने सागर की नायक किन्नर किरण पर गंभीर आरोप लगाए थे. रानी ठाकुर का आरोप है कि किरण द्वारा मोना पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे मानसिक प्रताड़ना में आकर मोना ने यह कदम उठाया. इन आरोपों को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं.

एसपी से जवाब तलब

शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह मामला केवल आत्महत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन, धार्मिक स्वतंत्रता और मानसिक उत्पीड़न जैसे संवेदनशील पहलू जुड़े हुए हैं. आयोग ने दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और यह स्पष्ट करने को कहा है कि अब तक की जांच में क्या कार्रवाई की गई है तथा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

रानी ठाकुर को किन्नर समाज से निष्कासित करने का सुनाया था फैसला

बता दें कि इस मामले को लेकर बीते दिनों सागर में भारी बवाल देखने को मिला था. प्रदेशभर से बड़ी संख्या में किन्नर सागर पहुंचे थे और यहां किन्नर पंचायत का आयोजन किया गया था. पंचायत के दौरान मामले पर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद किन्नर समाज ने किन्नर रानी ठाकुर को समाज से बाहर करने का निर्णय लिया था. इस निर्णय के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया था तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे.

किन्नर रानी ठाकुर का आरोप

वहीं किन्नर रानी ठाकुर लगातार इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करती रही हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया गया होता, तो मोना की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद अब आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है.

सागर और टीकमगढ़ पुलिस महकमे में हलचल तेज

अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इस एक्शन के बाद यह देखना अहम होगा कि पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या आरोपों की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो पाती है या नहीं. फिलहाल आयोग के नोटिस के बाद सागर और टीकमगढ़ पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई.

Source: https://ddnews.gov.in/why-cant-we-ask-dogs-to-carry-certificates-for-walking-the-supreme-court-slammed-the-petitioners-suggestion/

याचिकाकर्ता के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, हम कुत्तों से सर्टिफिकेट लेकर चलने को क्यों नहीं कह सकते

4 hours ago

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लावारिस कुत्तों के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके इलाके में बहुत सारे लावारिस कुत्ते हैं, जो पूरी रात एक-दूसरे का पीछा करते रहते हैं, भौंकते हैं, जिससे उन्हें नींद नहीं आती और उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते।

याचिकाकर्ता ने इस मामले में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनका कहना कि वे केवल वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। एनएचआरसी को भी भी पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स (एबीसी नियम) केवल एक खास दायरे में काम करते हैं। कुत्तों को स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन के बाद फिर से छोड़ दिया जाता है।

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि दुनियाभर में यह स्वीकार किया जाता है कि लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी नसबंदी व्यवस्था जरूरी है। जयपुर और गोवा जैसी जगहों में यह सिस्टम सफल रहा है, लेकिन ज्यादातर शहरों में स्टरलाइजेशन प्रभावी नहीं हो पा रहा। स्टरलाइजेशन से कुत्तों की आक्रामकता कम होती है, लेकिन समस्या यह है कि कई शहरों में सही ढंग से यह नहीं हो रहा। इसे बेहतर बनाने के लिए पारदर्शिता लानी होगी और लोगों को जवाबदेह बनाना होगा।

एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां लोग उन लावारिस कुत्तों की रिपोर्ट कर सकें जिनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है। इसे किसी वेबसाइट पर दर्ज किया जाए और कोई विशेष अथॉरिटी हो जो ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करे।

प्रशांत भूषण के इस सुझाव पर जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि हम कुत्तों से खुद सर्टिफिकेट लेकर चलने को क्यों नहीं कह सकते। प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत संदेश दे सकती हैं। उदाहरण के लिए इसी कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों के काटने के लिए फीडर्स को जिम्मेदार ठहराया जाए, जो शायद व्यंग्य था। जस्टिस विक्रम नाथ ने स्पष्ट किया कि यह व्यंग्य में नहीं कहा गया था, बल्कि बहुत गंभीरता से कहा गया था।

इसके अलावा, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मामले पर किए गए पॉडकास्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूर्व मंत्री की तरफ से पेश हुए वकील राजू रामचंद्रन से कहा कि थोड़ी देर पहले आप कोर्ट से टिप्पणियों को लेकर सावधान रहने की बात कर रहे थे। क्या आपको पता है कि आपके क्लाइंट किस तरह की बातें कर रही हैं? आपके क्लाइंट ने कोर्ट की अवमानना की है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, यह हमारी दरियादिली है। क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? वह क्या कहती हैं और कैसे कहती हैं। आपने टिप्पणी की कि कोर्ट को सावधान रहना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर आपकी क्लाइंट जिसे चाहे और जिसके बारे में चाहे, हर तरह की टिप्पणियां कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मानव सुरक्षा, एबीसी नियमों के क्रियान्वयन और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर विचार कर रहा है। सुनवाई आगे जारी रहेगी। (इनपुट-आईएएनएस)

Source: https://www.joharlive.com/news/supreme-court-takes-a-tough-stance-on-stray-dog-attacks-hinting-at-fixing-responsibility-on-dog-feeders/

आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी तय होने के संकेत

By Anu Singh January 20, 2026 3 Mins Read

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि किसी हमले में किसी व्यक्ति की चोट या मौत होती है, तो नगर निकायों के साथ-साथ डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसकी पिछली टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा, अदालत इस विषय को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है और अदालत जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगी। पीठ ने संकेत दिया कि इस मामले में निजी पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

28 जनवरी को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। उस दिन अदालत एमिकस क्यूरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के वकील और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की दलीलें सुनेगी। एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने बताया कि अभी सात राज्यों से जानकारी आना बाकी है।

कोर्ट में तीखी बहस, अलग-अलग पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से एडवोकेट हर्ष जैदका, डॉग लवर्स और एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण तथा मेनका गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने अपनी दलीलें रखीं।

पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि आवारा कुत्तों के हमलों से बच्चों और आम नागरिकों की जान खतरे में है और प्रशासन समय रहते प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा है। कुछ वकीलों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन से जोड़ा और कहा कि यदि आवारा कुत्तों के कारण किसी की मौत होती है, तो राज्य सरकार मुआवजे की जिम्मेदार होगी।

वहीं, डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया कि संविधान सभी जीवों के प्रति करुणा रखने का निर्देश देता है। उनका तर्क था कि समस्या का समाधान कुत्तों को मारना नहीं, बल्कि प्रभावी नसबंदी, टीकाकरण और कचरा प्रबंधन है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में नसबंदी कार्यक्रमों से आवारा कुत्तों की संख्या और आक्रामकता कम हुई है।

रेबीज और इलाज पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान रेबीज के इलाज और रोकथाम को लेकर भी बहस हुई। कुछ वकीलों ने कहा कि रेबीज 100 प्रतिशत रोकी जा सकने वाली बीमारी है, लेकिन भारत में प्रभावी रोकथाम नीति का अभाव है। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और समय पर इलाज न मिलने के आरोप भी लगाए गए।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस मेहता ने कुछ मामलों में हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत किसी विशेष मौत के कारणों पर टिप्पणी की अनुमति नहीं देगी। वहीं, जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि अदालत की टिप्पणियां व्यंग्य नहीं थीं और उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

पीठ ने दोहराया कि पिछली सुनवाई में यह संकेत दिया गया था कि आवारा कुत्तों के हमलों में नगर निकायों के साथ-साथ डॉग फीडर्स की भी जिम्मेदारी तय हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर संतुलन और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें लगभग पूरी कर ली हैं और 28 जनवरी को होने वाली सुनवाई में राज्यों और संबंधित संस्थाओं से ठोस जवाब और समाधान की उम्मीद जताई है।

The Wire, Online News, 21/01/2026

Source: https://m.thewire.in/article/ptiprnews/brmgsu-leads-human-rights-social-security-meet-for-unorganised-workers/amp

BRMGSU Leads Human Rights & Social Security Meet for Unorganised Workers

PTI | 5 hours ago

New Delhi [India], January 20: Hooghly witnessed a massive mobilisation of unorganised sector workers as a large-scale conference on Human Rights Awareness and Social Security for Unorganised Sector Workers – 2026 was held at Dunlop Maidan. More than 20,000 workers participated, most of them railway Mall Godam (goods shed) labourers from different districts of West Bengal. The conference focused on strengthening awareness around labour rights, human dignity, and access to social security for workers outside formal employment structures. It was jointly organised by the Bharatiya Railway Mall Godam Shramik Union (BRMGSU) and the Bharatiya Labour Union, with support from SGT University and Nomo Foundation. The objective was to create a collective platform where workers could better understand labour laws, human rights provisions, and welfare schemes meant for their protection.

BRMGSU Background: The Bharatiya Railway Mall Godam Shramik Union has been actively working for the welfare and rights of railway goods shed labourers across India. Over the years, the union has consistently raised issues related to job security, minimum wages, occupational health and safety, and social protection for Mall Godam workers, many of whom operate in highly informal and vulnerable conditions. Through sustained advocacy, dialogue with authorities, and grassroots mobilisation, BRMGSU has emerged as a strong and credible voice for unorganised railway labourers.

The programme was inaugurated by Dr. Parimal Kanti Mondal, President of BRMGSU, who highlighted the long-standing challenges faced by unorganised workers, including lack of job security, inadequate wages, limited healthcare facilities, and absence of social protection. He stressed that unity, legal awareness, and organised action are essential to securing dignity and justice for Mall Godam labourers.

The conference was attended by Priyank Kanoongo, Hon'ble Member of the National Human Rights Commission, as Chief Guest. Addressing the gathering, he stated that labour rights are an integral part of human rights. Referring to his recent visits to railway goods sheds across West Bengal, he shared insights from direct interactions with workers and assured that the issues raised would be pursued through appropriate institutional mechanisms.

Sheo Prasad Tiwari, National General Secretary of TUCC, attended as Special Guest and highlighted the importance of collective struggle and strong trade union movements in protecting workers' rights.

Senior officials from the Ministry of Labour addressed the gathering on key enforcement and welfare issues. Anil Jena spoke on labour law enforcement and statutory rights, while Dwipannita Jena highlighted occupational health and safety concerns. Shitangshu Tai elaborated on welfare schemes and social security benefits available to unorganised workers.

Legal perspectives were shared by Sanjay Ghosh and Kobir Ghosh, who stressed the importance of legal awareness and judicial support in strengthening the fight for labour rights.

The conference concluded with a call for sustained unity and organised efforts, led by Indu Sekhar Chakroborty, General Secretary of BRMGSU, reaffirming commitment to the ongoing movement for human rights, social security, and dignity of labour for unorganised sector workers.

(Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with PNN and PTI takes no editorial responsibility for the same.). PTI PWR

This is an auto-published feed from PTI with no editorial input from The Wire.

This article went live on January twentieth, two thousand twenty six, at thirty-one minutes past three in the afternoon.